

INDIA SOLOMON HOLDINGS LIMITED

(Formerly known as Solomon Holdings Private Limited consequent up on its Name Change and Conversion as well as Merger of India Stuff yarn Limited)

Regd.Off:Room No.401, 3198/15,Sangatrashan,Paharganj,NewDelhi-110055

Corporate Office: 47/18, Metro Station Rajendra Place New Delhi, New Delhi, India, 110060

EmailId:indiasolomonh121@gmail.com,ContactNo:8920674883

CIN: L65993DL2000PLC104410, Website: www.indiasolomon.in

Date: 19.05.2026

To,
The Manager- Compliance Department
Metropolitan Stock Exchange of India Limited
205(A), 2nd Floor, Piramal Agastya Corporate Park
Kamani Junction, LBS Road, Kurla (West)
Mumbai - 400070.

SYMBOL: ISHL (INDIA SOLOMON HOLDINGS LIMITED) EQ - ISIN – INE00WT01013.

Subject: Submission of Extract of Newspaper Publication of audited (Standalone and Consolidated) Financial Results for the quarter ended on 31st March, 2026.

Dear Sir/Madam,

With reference to the above captioned subject, please find herewith enclosed copies of Newspaper Publication of audited (Standalone and Consolidated) Financial Results for the quarter ended on 31st March, 2026. Pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The Financial Results was published in one English Newspaper “English Daily Open Search” and in one Hindi Newspaper “Hindi Daily Open Search” in the language of the region where the registered office situated. The web link for the direct access to the abovementioned newspaper advertisement is <https://www.opensearch.co.in/32527/> and <https://www.opensearch.co.in/32525/>. You are requested to take the above on your records and acknowledge the same.

You are requested to take the above on your records and acknowledge the same.

Thanking You.

**For and on behalf of Board of Directors
INDIA SOLOMON HOLDINGS LIMITED**

**PANKAJ SAXENA
Managing Director
DIN: 08162590**

Place: New Delhi

मेट्रो विस्तार और ओबीसी आयोग को हरी झंडी, योगी कैबिनेट ने दी अहम फैसले को मंजूरी

लखनऊ (एजेंसी)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं, ऊर्जा व्यवस्था, नगरीय परिवहन और पंचायत आरक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने पूर्वांचल में बिजली आपूर्ति को मजबूत करने, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने और महानगरों में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में बड़े फैसले लिए गए।

मंत्रिमंडल के निर्णयों को आगामी वर्षों में प्रदेश के विकास और निवेश के लिहाज से अहम माना जा रहा है। बैठक में मिर्जापुर में 765/400 केवी क्षमता वाले विद्युत सकलन उपकेंद्र और उससे जुड़े पारेषण लाइनों की स्थापना को स्वीकृति दी गई। करीब

सरकार ने पूर्वांचल में बिजली आपूर्ति को मजबूत करने, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने और महानगरों में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में बड़े फैसले लिए गए

2799.47 करोड़ रुपए की इस परियोजना से प्रदेश में उत्पादित बिजली की निकासी और आपूर्ति व्यवस्था अधिक मजबूत होगी। सरकार का कहना है कि इससे घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बेहतर और निर्बाध बिजली मिल सकेगी। साथ ही औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के शहोद पथ स्थित नए परिसर में 1,100 शै्याओं वाले



अत्याधुनिक आपात चिकित्सा केंद्र, शिक्षण भवन और बाह्य रेगो विभाग (ओपीडी) भवन के निर्माण को भी मंजूरी दी। लगभग 855 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना से राजधानी समेत आसपास के जिलों के मरीजों को ऊन्नत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। सरकार का मानना

है कि मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल का विस्तार आवश्यक हो गया था। इससे प्रयागराज मंडल के कई जिलों के लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। बैठक में आगरा और लखनऊ में मेट्रो परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। आगरा में दूसरे गलियारे के लिए मेट्रो स्टेशन और ऊपरी मार्ग निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण को स्वीकृति दी गई। वहीं,

लखनऊ में चारबाग से वसंतकुंज तक पूर्व-पश्चिम गलियारे के निर्माण के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर सहमति दी गई। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 5,801 करोड़ रुपए बताई गई है। बैठक में पशु चिकित्सा के विद्यार्थियों के प्रशिक्षण भत्ते में वृद्धि करने का निर्णय भी लिया गया। सरकार का कहना है कि इससे

विद्यार्थियों को आर्थिक सहयोग मिलेगा और पशु चिकित्सा सेवाओं में दक्ष मानव संसाधन तैयार करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करने के लिए 'उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग' के गठन को मंजूरी दी गई।

आयोग पंचायतों में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का अध्ययन कर आरक्षण संबंधी सुझाव देगा। आयोग में पांच सदस्य होंगे, जिनमें एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया जाएगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए मिर्जापुर जिले में 'सरदार पटेल एपेक्स विश्वविद्यालय' की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने को मंजूरी दी। यह विश्वविद्यालय चुनाव तहसील के समसपुर गांव में स्थापित किया जाएगा।

‘जनता दर्शन’ में सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्या, बिहार से पहुंची महिला का भी किया अभिवादन

लखनऊ (एजेंसी)



उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यस्ततम दिनचर्या के बीच भी सोमवार को 'जनता दर्शन' किया। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए फरियादियों से मिले और हर किसी की समस्या सुनी। मुख्यमंत्री ने सभी से कहा कि जनसेवा, सुरक्षा व सुशासन सरकार का संकल्प है।

आपकी हर उचित समस्या का समाधान होगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर समस्याओं के निस्तारण का भी निर्देश दिया। 'जनता दर्शन' में बिहार से भी एक महिला मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचीं, मुख्यमंत्री ने उनका अभिवादन कर कुशलक्षेम पूछा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी के प्रार्थना पत्र लेने के उपरंत सम्बंधित जनपदों के अधिकारियों को प्रकरण की जांच करकर पीड़ितों को न्याय दिलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक स्वयं मामलों पर नजर रखें और पीड़ितों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा

कि हर जरूरतमंद की समस्या का समाधान हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देशित किया कि पूरी तत्परता व संवेदनशीलता से सुनिश्चित करें कि बिना भेदभाव सभी को न्याय मिले। हर पात्र को योजनाओं का लाभ मिले, जरूरतमंदों के समुचित इलाज की व्यवस्था हो, जमीन कब्जाने वाले भू माफिया व दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री ने राजस्व और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में शीघ्रता से निस्तारण के निर्देश दिए।

'जनता दर्शन' में सीएम योगी की प्रशंसक एक महिला बिहार से आई थीं। मुख्यमंत्री सभी की समस्या सुनते हुए उनके पास भी पहुंचे। पूछा कि क्यों से आई हैं, आपको क्या परेशानी है। इस पर महिला ने, 'महाराजराज जी, प्रणाम। हम बिहार से आइल बानी।

बिहार : पुलिस मुठभेड़ में ज्वैलरी की दुकान में लूट का आरोपी घायल, पैर में लगी गोली



सिवान (एजेंसी)

बिहार पुलिस अब अपराधियों के खिलाफ एक्शन में दिख रही है। पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस बीच, सिवान जिले में सोमवार को पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक वांछित अपराधी के घायल होने की सूचना है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस को सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक फरार अपराधी उत्तर प्रदेश की तरफ से अपने घर जा रहा है। उक्त सूचना पर मैरवा थाना पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत सघन

वाहन जांच अभियान चलाया गया। वाहन जांच के दौरान बेदौली मोड़ स्थित छठ घाट के समीप पुलिस ने एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया। पुलिस टीम को देखते ही उक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी गई। स्थिति को गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षण एवं अपराधी को नियंत्रित करने के लिए जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई। घायल अपराधी को तत्काल इलाज के लिए सरकारी सुरक्षा के बीच पीएमसीएच, पटना भेजा गया, जहां उसका इलाज

ओमप्रकाश राजभर का सपा पर बड़ा हमला, बोले- पीडीए की आड़ में सिर्फ ‘यादव’ ढूंढना बंद करें अखिलेश

लखनऊ (एजेंसी)

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने आरक्षण के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजभर ने सपा के पीडीए को 'पार्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश' करार दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को अपने पीडीए की आड़ में सिर्फ 'यादव' ढूंढना बंद करना चाहिए।

अखिलेश यादव ने आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर राज्य सरकार पर हमलावर हैं। वे इस मुद्दे पर 20 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसका विषय 'पीडीए ऑडिट, आरक्षण की लूट' रखा गया है। अखिलेश यादव ने एक 'एक्स'



पोस्ट में लिखा, 'भाजपा पीडीए के आरक्षण की लूट का गैंग है।' ओमप्रकाश राजभर ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर

राजभर ने सपा के पीडीए को 'पार्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश' करार दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को अपने पीडीए की आड़ में सिर्फ 'यादव' ढूंढना बंद करना चाहिए। अखिलेश यादव ने आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर राज्य सरकार पर हमलावर है

पोस्ट किया, लगता है कि अखिलेश यादव का हाल एकदम ठीक नहीं है। हम उनसे सवाल पूछते हैं और वो साधु संतों को गोली देते हैं।

हम अपनी बात का जवाब देते हैं और वो साधु-संतों को इसमें घसीटते हैं। आप और आपके लोग बात-बात पर साधु-संतों को गाली देना बंद करें। अभी तो कम दुर्गति हुई है, आगे आप लोगों को बड़ा श्राप भोगना पड़ेगा। मंत्री राजभर ने पोस्ट में आगे लिखा, अखिलेश यादव, अब तो आप

विषम में हैं, ज्यादातर फ्री ही रहते होंगे। पुराने दिनों को याद कीजिए और 2013 के उस वाले कांड का पर्दाफाश कर दीजिए कि कैसे आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पर एक ऐसे व्यक्ति को बिटा दिया था, जो हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी था।

और हैरान करने वाली बात ये है कि ये काम आपने 80 से अधिक योग्य उम्मीदवारों के साथ छल करके किया था। मगर, आपको इस ढीठता भरी नियुक्ति को 14 अक्टूबर



रखें, क्योंकि समाजवादी पार्टी में अविश्वास की स्थिति है। इसी कारण लोग भाग रहे हैं। सोमेंद्र तोमर ने विभागों के बंटवारे पर कहा, मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उनके सभी दिशा-निर्देशों के आधार पर हम कार्य करेंगे। जो भी दायित्व मिला है, उसका ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। कैबिनेट विस्तार के बाद नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा होने पर मंत्री ओपी राजभर ने कहा, सरकार ने 60 मंत्रियों की संवैधानिक व्यवस्था को पूरा किया है और सभी को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है। उन्होंने आगे कहा, 'विषम इतना परेशान था कि उनकी नींद और भूख उड़ गई थी, लेकिन अब वे उस चिंता से मुक्त हो गए हैं

2015 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने 'अवैध', 'मनमाना' और संविधान के अनुच्छेद 316 का उल्लंघन बता दिया था। राजभर ने कहा, 'नियुक्तियों में हेराफेरी वाली आपकी सरकार के दौरान बड़े-बड़े कारनामे किए हैं।

सीएम सम्राट चौधरी से मिले गौतम अदाणी, राज्य में 60 हजार करोड़ के निवेश का ऐलान

पटना (एजेंसी)

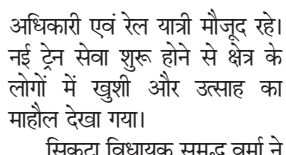


अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने रविवार को सारण के मस्तीचक में अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल में अदाणी आई केंयर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ अदाणी फाउंडेशन की चेयरपर्सन प्रीति अदाणी भी मौजूद रहीं। सारण में आई केंयर प्रोजेक्ट के उद्घाटन के बाद गौतम अदाणी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। सम्राट चौधरी ने गौतम अदाणी के साथ मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। मुख्यमंत्री ने लिखा कि देश के विख्यात उद्योगपति और अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी ने

शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने बिहार के विकास के लिए हसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं, गौतम अदाणी ने भी सोशल मीडिया पर शेयर एक पोस्ट में लिखा कि आज पटना में बिहार के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ हुई सांख्यिक मुलाकात ने राज्य के उज्ज्वल भविष्य में हमारे विश्वास को और मजबूत किया है।

चम्पारण : नरकटियागंज से दरभंगा और सिकटा से मुजफ्फरपुर के लिए नई ट्रेनें शुरू

पश्चिमी चंपारण (एजेंसी)



पश्चिम चम्पारणवासियों के लिए सोमवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जब क्षेत्र को दो नई ट्रेनों की सौगात मिली। नरकटियागंज जंक्शन से दरभंगा जंक्शन तथा सिकटा से मुजफ्फरपुर जंक्शन के लिए नई ट्रेनों का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, सांसद सुनील कुमार एवं सिकटा विधायक समुद्ध वर्मा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर ट्रेनों को रवाना किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि, रेल

अधिकारी एवं रेल यात्री मौजूद रहे। नई ट्रेन सेवा शुरू होने से क्षेत्र के लोगों में खुशी और उत्साह का माहौल देखा गया।

सिकटा विधायक समुद्ध वर्मा ने कहा कि सिकटा विधानसभा क्षेत्र लंबे समय से बेहतर रेल कनेक्टिविटी से वंचित था। आज का

दिन क्षेत्रवासियों के लिए बेहद खुशी और गौरव का दिन है। अगर यह ट्रेन सेवा पटना तक विस्तारित हो जाती, तो क्षेत्र के लोगों को और अधिक सुविधा मिलती, क्योंकि सिकटा विधानसभा क्षेत्र से पटना के लिए अब तक कोई सीधी ट्रेन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री एवं रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि नरकटियागंज से दरभंगा और सिकटा से मुजफ्फरपुर के लिए शुरू की गई ट्रेनें चम्पारणवासियों के लिए बड़ी सौगात हैं।

सविधान और धर्मनिरपेक्षता से समझौता देशहित में नहीं, पश्चिम बंगाल हिंसा पर मायावती की सरकारों को नसीहत

लखनऊ (एजेंसी)

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने देश की धर्मनिरपेक्ष पहचान, संविधान की मर्यादा और पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा को लेकर केंद्र व राज्य सरकारों को नसीहत दी है। मायावती ने कहा कि भारत की वैश्विक पहचान बाबा साहेब के संविधान और सेक्युलर मूल्यों के कारण है, इसलिए सभी सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे किसी भी प्रकार के धार्मिक, जातीय या राजनीतिक भेदभाव से बचें तथा सभी नागरिकों की जान-माल और मजहबी आजादी की समान रूप से रक्षा सुनिश्चित करें।

मायावती ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि जैसा कि सर्वविदित है कि अपने भारत देश की तुनिया भर में अच्छे एवं अनोखी मानवतावादी पहचान खासकर परमपूज्य बाबा साहेब ड. भीमराव



अम्बेडकर के अनुपम संविधान को लेकर ज्यादा है, जो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त पर आधारित है अर्थात् यहां रहने वाले विभिन्न धर्मों के मानने वाले सभी लोगों को एक-समान आदर-सम्मान देना है। उन्होंने कहा कि देश का मिश्रण भी अधिकतर ऐसे ही उच्च मानवीय गुणों पर आधारित सभी धर्मों के मानने वालों को उनके जान, माल व मजहब की आजादी एवं सुरक्षा आदि सुनिश्चित करता है। इसके निर्धारित व बताये हुये रास्तों पर चलना सभी सरकारों की ही नहीं बल्कि सभी नागरिकों की भी परम

व प्रमुख जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं बल्कि यह भी सर्वविदित ही है कि यही वह सुरक्षा कवच है जिसके सहारे विदेशों में भारत-विरोधी प्रोपगण्डा आदि का देश हमेशा बखूबी सामना करता है, किन्तु केन्द्र व सभी राज्य सरकारों का यह दायित्व/ जिम्मेदारी बनती है कि वे ऐसा कुछ भी ना करें और ना ही वैसे कुछ होने दें जिससे देश व खासकर भारत सरकार से इसके बारे अप्रिय स्वाल-जवाब हो। उन्होंने कहा कि खासकर पश्चिम बंगाल में चुनाव उपरान्त जारी हिंसा की सर्वत्र रही

चर्चाओं में भी विशेषकर मा. हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद सरकारों को इसके प्रति सतर्क व अराजकता के विरुद्ध सख्त हो जाना चाहिये, ताकि किसी भी सरकार के ऊपर संकीर्ण राजनीति, धार्मिक भेदभाव, जातीय द्वेष व पक्षपात आदि का दोष लगे, यह अति-चिन्ता की बात जरूर होनी चाहिये।

मायावती ने कहा कि इसके साथ ही, व्यापक जनहित व जनसुरक्षा के मद्देनजर स्थापित नियम-कानूनों के अनुपालन या तत्सम्बंधी नये कानून आदि बनता है तो उसका अनुपालन सभी धर्मों के लोगों पर एक समान रूप में होना चाहिये अर्थात् संविधान व क़ानून की मान-मर्यादाओं को बरकरार रखने के लिये जरूरी है कि कानूनों का इस्तेमाल धार्मिक व जातीय भेदभाव/ पक्षपात व द्वेष के बिना हो, ताकि सरकारें सर्वसमाज व सर्वधर्म हितैषी हों और लोगों को लगे भी तथा जिससे सरकारों की संवैधानिक गुडविल प्रभावित ना हो तो यह उचित होगा।